क्या-क्या शर्तें रखी हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (घ) यू० एस० व्यापार तथा प्रतियोगी अधिनियम, 1988 के सुपर 301 प्रावधान 31.12.1990 से समाप्त हो गए।

26 मई, 1991 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने अपने व्यापार कानून के स्पेशल 301 प्रावधानों के अंतर्गत भारत के विरुद्ध जांच प्रारंभ की थी। संयुक्त राज्य ने भेषजीय पदार्थों और अन्य परौद्योगीकी के लिए उत्पाद एकस्व संरक्षण के क्षेत्र तथा अवधि, अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्थाओं, कॉपीराइट को लागू करने तथा मोशन पिक्चर्स के लिए अधिक बाजार पहुंच आदि के मामले उठाये थे।

सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कापीराइट अधिनियम में कुछ प्रस्तावित संशोधनों सहित ट्रेडमार्क और कापीराइट से संबंधित हमारे कानून पर्याप्त हैं। मोशन पिक्चर्स और वीडियो के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए भी एक निर्णय लिया जा चुका है। जहां तक पेटेन्ट के मुद्दे का संबंध है, संयुक्त राज्य का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है। कि यह बहुपक्षीय वार्ताओं का विषय है और ये वार्ताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

दिनांक 26 फरवरी, 1992 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ धारा-301 के अधीन जांच को समाप्त कर देने के निर्णय की घोषणा कर दी है।

प्याज का निर्यात

1827. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने प्याज उत्पादकों को यह आवश्वासन दिया था कि प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक इस प्रतिबन्ध को हटा लेगी; और

(ग) सरकार प्याज-उत्पादकों के हित में प्याज के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्याज के निर्यात को बढ़ाने तथा साथ ही साथ उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से प्याज के निर्यात को नाफेड के माध्यम से सरणीकृत किया गया था। सरणीकरण अभिकरण के रूप में नाफेड ने प्याजों का वैज्ञानिक भंडारण, अनुसंधान और विकास सुविधाएं, नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्याज के उपजकर्त्ताओं को शिक्षित करना, प्रतियोगी दरों पर रेल द्वारा प्याज की ढुलाई, नौवहन से संबंधित सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था पैकेजिंग स्थितियों में सुधार आदि जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय किए हैं।

Export of Substandard Food Materials

1828. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that number of food materials exported by Government to certain foreign countries have been found sub-standard and unfit for human consumption;

(b) whether it is also a fact that import of such food materials has been stopped by these countries; and

(c) if so, what are the details in this regard and what measures do Government take to set things right?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) to (c) During February and March 1991, some export consignments shipped from India, mainly food items, were detained at various ports in the United States. Detention of these consignments at US ports did not mean that the consignments were rejected. Detentions meant that the consignments were not cleared automatically but only after testing, and if need be, after re-conditioning. The list of consignments detained at US ports and the reasons for detention were conveyed to the concerned trade associations, export promotion councils and

Government agencies so that the exporters could be sensitized to the need to upgrade the quality of export consignments for meeting the requirements of US Government in respect of imports in the US.

High Commission of India, Nicosia, Cyprus, however, reported that two consignments of cashew kernels exported from India were inspected by Cyprus health Authorities and found insect damaged and unfit for human consumption. The details of the consignments being: (1) 400 cartons plain cashew kernels shipped on 20th August, 1991; and (2) 674 cartons of roasted and salted cashew kernels shipped on 30th August, 1991.

In the case of first consignment, shipment effected after approval of the sample by Cyprus Health Authorities and after obtaining all the required certificates and in the case of second consignment, shipment was effected after obtaining all the documents asked for by the buyers. Exporters maintain that they have exported only quality products and the problems created by the buyers was due to fall in cashew kernel prices subsequent to the contract. Since they have received the payments in full, they are determined to face any consequences through legal means.

No report has been received by Government about any stoppage of import of food materials from India.

The Commodity Boards, Export Promotion councils and Export Development Authorities keep the exporters, informed of the quality standards set up in EEC countries and by US Food & Drugs Administration for the import of food items into their countries so that exporters maintain the standards expected in those countries.

इंडोनेशिया द्वारा मांस का आयात

1829. **डा० बापू कालदाते :**
डा० एन० तुलसी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया ने भारत से मांस का आयात करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्डोनेशिया को पुनः मांस का निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) इन्डोनेशिया भारत से मांस का आयात नहीं करता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

Demand of Leather Products by Germany

1830. DR. BAPU KALDATE:
SHRI P. UPENDRA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great demand of leather products from Germany;

(b) if so, what is the demand from Germany during the year 1991-92 and how much actual export has been made, so far; and

(c) whether the export of leather and leather goods has dwindled during the last few months putting the leather industry in doldrums?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) While there is no estimate of the total demand of leather products in Germany, that country was our biggest market in 1990-91. Our exports to Germany in 1991-92 upto November, 1991 was Rs. 407.10 crores.

(c) The total exports of leather and leather products as well as exports to Germany during the current year upto November, 1991 (for which figures are available) have been higher than the